

266  
266  
उत्तराखण्ड शासन,  
समाज कल्याण अनुभाग-01,  
संख्या-3730/XVII-1/2013-13(45)/2013,  
देहरादून, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013.

### अधिसूचना

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या-2458/एम0एस0/2013 में समाज विकास एवं कल्याण समिति बनाम राज्य व अन्य में याची द्वारा यह अनुतोष चाहा गया कि-

- to issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondent not to stop issuance of the scheduled caste certificates to the scheduled caste/Shilpkars of the (sub) caste Koli.
- to issue a writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondent to keep continue issuing the scheduled caste certificates to the persons/Shilpkars of the sub caste Koli.
- to issue any other writ order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the circumstances of the present case.
- to allow this writ petition and award the cost of it in favour of the petitioners.

उत्तराखण्ड में निवासरत शिल्पकार जाति के लोगों की अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में प्रशासनिक स्तर (यानि जिला एवं तहसील स्तर) पर कठिनाई आ रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि शासनादेश के क्रम संख्या 64 में शिल्पकार जाति के श्रेणी दर्शाया गया है, उसमें सम्मिलित विभिन्न जातियों का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया जबकि उत्तराखण्ड में शिल्पकार नाम की अलग से कोई जाति न होकर "शिल्पकार" जातियों का एक समूह है।

शिल्पकार जाति में सम्मिलित उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिए शासन स्तर से दिशा निर्देश निर्गत करने हेतु समय-समय पर सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों जैसे श्री हरि सिंह, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड कोली समाज विकास एवं कल्याण समिति (रजिस्टर्ड), देहरादून एवं श्री हीरालाल टम्टा, महासचिव, प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति, पौड़ी-गढ़वाल, उत्तराखण्ड, तत्कालीन जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों के माध्यम से शासन से मांग की जाती रही है। तत्कालीन प्रमुख सचिव उत्तरांचल सचिवालय द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों (कुमायूं/गढ़वाल) को निर्देशित किया गया कि वास्तव में शिल्पकार अनेक प्रकार दस्तकारी में संलग्न जातियों का एक समूह है जैसे लोहार, टम्टा, औजी, बेड़ा, इत्यादि।

अतः पूर्व में इस समुदाय की जो व्याख्या दी गई है, वही उपयुक्त मानी जाय।



निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा अप्रैल, 1986 में शिल्पकार जाति की अन्य जातियों के नाम का उल्लेख किया गया है। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा शासन के पत्र संख्या-148, दिनांक 14.02.2008 के द्वारा उत्तराखण्ड के गढ़वाल/कुमायूं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में मूलतः निवास करने वाले बढई, लोहार, सोनार, दर्जी, गद्दी केवट, धुनार, ताम्रकार (टम्टा), मिस्त्री आदि का काम करने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (शिल्पकार) का प्रमाण-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में शिल्पकारों की सभी उपजातियों को उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने का अनुरोध शासन से किया गया है।

मा0 लोकायुक्त उत्तराखण्ड देहरादून में दायर परिवाद संख्या-284 वर्ष 2005 शिकायतकर्ता श्री बृजमोहन पुत्र श्री केवल राम, ग्राम झण्डीचौड़, कोटद्वार, जिला-पौड़ी के प्रतिवेदन (45/2007) में स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गये हैं कि पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत लोहार, सुनार, बढई, मिस्त्री, दर्जी आदि पूर्व से अनुसूचित जाति (शिल्पकार) की श्रेणी में आने से इन वर्गों के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (शिल्पकार) की सभी सुविधायें शासन द्वारा दी जा रही है। ये जातियाँ मैदानी क्षेत्र की न होकर पर्वतीय मूल की रही है तथा पर्वतीय मूल की जातियाँ पूर्व से अनुसूचित जाति में मानी गई है।

अतः उक्तानुसार ही उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट की गई जातियों को ही जाति प्रमाण-पत्र जारी किये जायें।

मा0 लोकायुक्त द्वारा दिनांक 14.02.2006 में तत्कालीन अपर सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपस्थित होकर उनके द्वारा वर्ष 1931 में देश में की गई जनगणना के सम्बन्ध में "Census of India" 1931 Part I Report, "United Province of Agra and Outh" Anthropological Survey of India द्वारा प्रकाशित पुस्तक "People of India" Part 3 व The Himalayan Gazetteer की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, यह कहा गया कि लोहार, बढई, मिस्त्री, दर्जी एवं टम्टा आदि जातियाँ अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। लोकायुक्त द्वारा यह इंगित किया गया कि मेरे समक्ष अन्य संगठनों, उत्तराखण्ड कोली समाज व प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति पौड़ी गढ़वाल द्वारा भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि बढई, लोहार, सुनार, बसेरा, ठठेरा, ताम्रकार इत्यादि शिल्पकारों की उपजातियाँ उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में सदैव से मानी जाती रही हैं और उनके साथ सवर्ण जातियों द्वारा छुआ-छूत का बरताव किया जाता है।

अतः उचित होता कि प्रशासन इस विषय में समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से मार्गदर्शन लेने के पश्चात सुस्पष्ट नीति निर्धारित करता ताकि पारित आदेशों में जो भ्रान्तियाँ, विसंगतियाँ उत्पन्न हुई है, उनका निराकरण सम्भव हो सकता। मा0 लोकायुक्त द्वारा निम्न संस्तुतियाँ की -

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून भारत सरकार के समाज कल्याण, मंत्रालय/अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार से विचार विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लें कि क्या उत्तराखण्ड प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमायूं मंडलों में निवास करने वाली अठपहरिया, औंजी, बढई, बेड़ा, भाट, कुम्हार, कोली, लोहार, रुड़िया, सुनार, पुहसी, जोगी, सोनार, छीपि, धोबी, कोलई, झुमरिया, टम्टा, कसेरा, धलोटी, बलूडिया, कोल्टा, हलिया, हुड़किया, भूल,



चुनरिया आदि जातियों को शिल्पकार की उप जातियां मानकर अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देना उचित हैं ?

यह अपेक्षा की गयी है कि शासन इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परतंत्र भारत में सन् 1921 की जनगणना की रिपोर्ट Vol XVI pro+II 1921 के पृष्ठ सं. 228 की TABLE XIII में Detail of the sub-castes of Hill depressed classes का उल्लेख है, जिसमें कोली, टम्टा, लौहार, अगरी तिरुवा आदि विभिन्न जातियों का समूह है जो वर्तमान में शिल्पकार जातियों के नाम से जानी जाती हैं।

सन् 1931 की जनगणना "CENSUS OF INDIA, 1931 UNITED PROVINCES OF AGRA AND OUDH, VOL. XVIII, PART I-REPORT BY A.C. TURNER, M.B.E., I.C.S., SUPERINTENDENT, CENSUS OPERATIONS" के पृष्ठ सं. 553-563 तक कुमाऊँ डिवीजन एवं टिहरी गढ़वाल राज्य, जिसे अब गढ़वाल मण्डल के नाम से जाना जाता है, में शिल्पकार जाति का उल्लेख है। इसमें भी उन्हीं जातियों को जिसमें कोली, टम्टा, लौहार, मिस्त्री आदि जातियां सम्मिलित हैं।

सन् 1941 की जनगणना V-TOWNS ARRANGED TERRITORIALY WITH POPULATION BY COMMUNITIES में शिल्पकार जाति के अन्तर्गत उप जाति का उल्लेख किया गया है।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के पत्र संख्या-5-140/07-Estt/(II), दिनांक 04.03.2009 के साथ संलग्न Communities, Segments, Synonyms, Sir Names and Titles Vol.-VIII के पृष्ठ-1769 से 1772 तक शिल्पकार की उपजातियों का स्पष्ट विवरण दिया गया है।

"CENSUS OF INDIA, 1961 Vol.-I Part-V-B(iii) showing consolidated statement of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, Denitrified communities and other communities of similar status in different status and census starting from 1921 by A.Mitra, ICS के पृष्ठ-86, 88, 90, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114 में भी शिल्पकारों की इन जातियों का स्पष्ट विवरण दिया गया है।

वर्ष 1961 की जनगणना से पूर्व जनगणना प्रणालियों को दिए गए निर्देशों में भी शिल्पकारों की उपजातियों का पर्यायवाची एवं वर्गीय नाम सहित स्पष्ट वर्गीकरण दिया गया है, जो कि Publication No. P.S.U.P.A.P Census 1960, 143000 में वर्णित है।

स्वतंत्र भारत के अखण्डित उत्तर प्रदेश में भी Publication No. U.P.-A.P.-1 CENSUS-1960-1,43,800 इन जातियों को भी शिल्पकार घोषित किया, तदनुसार इन उपजातियों का प्रमाणपत्र शिल्पकार नाम से समय-समय पर जारी हो रहे हैं, जिसमें कोली जाति भी सम्मिलित है।



तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-2/23-68/35/जनजाति (ह.क.) लखनऊ दिनांकित 07 अप्रैल, 86 में भी शिल्पकार जाति की उपजातियों का खुलासा करते हुए आदेश पारित किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून जो तदसमय पर्वतीय मंत्रालय के अधीन था, द्वारा भी दिनांक 24.04.1996 को श्री एस.एस. पांगती, प्रमुख सचिव द्वारा आदेश संख्या-223/उ.ख.दे./96 में भी भ्रान्तियों को दूर करने के लिए समस्त जिलाधिकारी गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल को यह लिखकर दिया कि "वास्तव में शिल्पकार अनेक प्रकार की दस्तकारी में संलग्न जातियों का समूह है, जैसे लौहार, रुडिया, टम्टा, औजी, बेड़ा इत्यादि।"

शासनादेश संख्या-12025/1/2008-एस.सी.डी. (आर.एल.सैल) भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1 दिनांकित 31.03.2008 में उल्लेख है कि शिल्पकार जाति उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति की सूची में क्रम सं. 64 पर अधिसूचित है। अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी करने तथा सत्यापन का कार्य सम्बन्धित राज्य सरकार का है। अतः राज्य सरकार अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित करे कि अधिसूचित जातियों के नाम से ही अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र निर्गत हों। अर्थात् भारत सरकार भी 2008 से यह चाह रही है कि शिल्पकार जातियों की स्थिति स्पष्ट की जाए, इसलिए भी उपरोक्त शासनादेश के क्रमांक-64-शिल्पकार के सम्मुख उपजातियों को खोला जाना आवश्यक है।

चूंकि उत्तराखण्ड सरकार ने मा. उच्च न्यायालय में रिट संख्या-26/2012 में भी कोली जाति को शिल्पकार मानते हुए सरकार का मत मा. उच्च न्यायालय में रखा है, अतः वर्तमान भ्रान्तियों को दूर करने के उद्देश्य से संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 के भाग-24-उत्तरांचल के क्रमांक-64 पर अंकित शिल्पकार जाति के अधीन निम्नलिखित उपजातियों को सम्मिलित किया जाता है-

क्रमांक	शिल्पकार जाति की उपजाति/पर्यायवाची नाम
1	आगरी या अगरी
2	औजी या बाजगी, ढोली, दास, दर्जी (जो अनुसूचित जाति के हैं)
3	अटपहरिया
4	बादी या बेड़ा
5	बेरी, बैरी
6	बखरिया
7	बढ़ई (जो अनुसूचित जाति के हैं)
8	बोरा (जो अनुसूचित जाति के हैं)
9	भाट
10	भूल, तेली (जो अनुसूचित जाति के हैं)
11	चनेला, चन्याल
12	चुनेरा, चुनियारा
13	डालिया
14	धलोटी
15	धनिक
16	धोनी

17	धुनिया
18	ढौडी या ढोंडिया
19	कोल्टा
20	होबियारा
21	हुडकिया, मिरासी (जो अनुसूचित जाति के हैं)
22	जागरी या जगरिया
23	जमारिया
24	कोली
25	कुम्हार (जो अनुसूचित जाति के हों)
26	लोहार, त्वार (जो अनुसूचित जाति के हों)
27	राज, ओड, मिस्त्री (जो अनुसूचित जाति के हों)
28	नाई (जो अनुसूचित जाति के हों)
29	नाथ या जोगी (जो अनुसूचित जाति के हों)
30	पहरी या प्रहरी
31	पातर
32	रौन्सल
33	रुडिया या रिंगालिया
34	सिरडालिया
35	सुनार या सोनार (यदि अनुसूचित जाति के हों)
36	टम्टा, तमोटा, ताम्रकार (जो अनुसूचित जाति के हों)
37	तिरुवा
38	तूरी

उपरोक्त वर्णित जातियों के व्यक्ति को जारी होने वाला अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र "शिल्पकार" जाति के नाम से जारी किया जाएगा।

उक्त शासनादेश केवल शिल्पकार जाति की भ्रान्तियों को दूर करने के लिए वर्गीकरण जारी किया जा रहा है। इसमें कोई नई जाति सम्मिलित नहीं की जा रही है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में अनुसूचित जाति (S.C.) अनुसूचित जनजाति (S.T.) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (O.B.C.) के लिए जाति प्रमाणपत्र निर्गत किए जाने के लिए पात्रता निर्धारण की शर्तों के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1118/XVII-1/2013-01(20)/2013, दिनांक 02.04.2013 यथावत् रहेगा।

उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

एस. राजू  
प्रमुख सचिव।



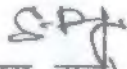
संख्या: 3730

(1)/XVII-1/2013-13(45)/2013, तददिनांक:

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव—महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव—माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3. निजी सचिव—समस्त माननीय मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
4. निजी सचिव—मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की, जनपद—हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड के सरकारी गजट में प्रकाशित करते हुए उसकी 200 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी—नैनीताल।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ✓ 12. निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

  
(एस. राजू)  
प्रमुख सचिव।